

# तुत्क्रह; l ekt ds fodkl e xj l jdkjh l xBuk dk ; kx nku Mxji g ftys ds l UnHkz

'kfDr fl g jkBkM+  
जनार्दन राय राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर

'kks/k l kjkd k% भारत विविध मान्यताओं का देश है जहाँ अनेक संस्कृति भाषा, धर्म, जाति, प्रजाति एवं सम्प्रदाय के लोग बसते हैं। इन विविधताओं का एक कारण भारत की भौगोलिक विशेषता कही जा सकती है, भौगोलिक विशेषता के कारण यहाँ अनेक ऐसी जनजातियाँ बसती हैं, जो आज भी सभ्यता एवं विकास से अत्यधिक दूर हैं। क्योंकि ये लोग सूदूर जंगलों पहाड़ों अथवा पठारी क्षेत्रों में अपना जीवन यापन करते हैं। इस कारण ये लोग अत्यधिक पिछड़े हुए हैं, इन्हें जनजाति आदिवासी गिरिजन पहाड़ी वन्यजाति आदिम जाति, पर्वतीय जाति, अनुसूचित जनजाति आदि नामों से पहचाना जाता है।

इस जनजातियों की सामान्य भाषा सामान्य संस्कृति, सामान्य भू-भाग एक नाम अन्तर्विवाह सामान्य निषेध, आर्थिक आत्म निर्भरता आदिक जैसी विशेषताएं पायी जाती हैं। जनजातियों की अनेक समस्याएं हैं जैसे— आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समस्या, धार्मिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चिकित्सा का एवं शिक्षा का अभाव दुर्गम निवास स्थान एवं एकीकरण की समस्या आदि पायी जाती हैं। जिन्हें दूर करने के लिए जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएँ, स्वतन्त्र भारत में प्रारंभ की गई। 26 जनवरी, 1950 से लागू भारतीय संविधान में राष्ट्र के कमजोर वर्ग के लोगों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक व सामाजिक हितों का विशेष ध्यान रखते हुए संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी प्रयास किये गये।

enly 'kcn% जनजातीय विकास, गैर-सरकारी संगठन, विकासात्मक गतिविधियाँ।

i l r k o u k %

जनजातीय क्षेत्रों का विकास देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के बाद से ही प्रमुख प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। किन्तु स्वतंत्रता के 66 वर्षों के पश्चात भी आदिवासी विकास के पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति अभी दूर है। निश्चय ही जनजाति समुदाय हमारे समाज का सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा है। उसे राष्ट्रकी मुख्यधारा से जोड़ना और उस तक विकास की पहल बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है।

यह कार्य अकेले सरकार या नौकरशाही द्वारा संभव नहीं है। इसी कारण गैर दृसरकारी संगठनों को जनजाति विकास में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि ये संगठन जनसहभागिता जन सहयोग के साथ दृसाथ स्थानीय लोगों की प्राथमिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिक संवेदनशील होकर कार्य करते हैं। साथ ही वर्तमान में यह बहस जोरों पर है कि सतत् विकास तथा सामाजिक तकनीकी हस्तान्तरण में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका दिनों-दिन बढ़ रही है।

प्रस्तुत अध्याय में जनजाति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारत एवं राजस्थान में जनजातीय परिदृश्य को स्पष्ट किया गया है। इसके साथ दृसाथ स्वतंत्रता पूर्व एवं पश्चात जनजातीय विकास की दशा और दिशा पर भी दृष्टिपात किया गया है। अध्याय के अंत में गैर-सरकारी संगठनों के अर्थ, इतिहास, इनकी कार्य प्रणाली को स्पष्ट किया गया।

xj & l jdkjh l xBu%

आज से तीन वर्ष पूर्व यानी 2009 में हमारे यहाँ करीब 33 लाख गैर-सरकारी संगठन थे। इस प्रकार 400 से भी कम लोगों पर एक एनजीओ था। हमारे यहाँ जितने प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनसे कई गुना अधिक गैर-सरकारी संगठन है। 7 जुलाई 2010 के b f M ; u , D l i l में पहली बार आकड़ों को प्रकाशित किया गया था।

दिसम्बर 2011 में भारत सरकार द्वारा किए गए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और नीदरलैण्ड पाँच सबसे बड़े दाता हैं जिनसे सर्वाधिक धन हमारे यहाँ सक्रिय एन.जी.ओ. को प्राप्त होता है। वर्ष 2009-10 के दौरान कुल मिलकर 10337 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्र के लिए बाहर से आए जिसमें उपर्युक्त पाँच देशों का हिस्सा 944 करोड़ रुपए था। यह धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों को मिली। बालकल्याण और शिक्षा संस्थानों के लिए क्रमशः 742 और 630 करोड़ रुपये मिले।

भारत के कार्यरत गैर-सरकार संगठन को कुल मिलाकर 2005-06, 2009-10 के पाँच वर्षों की अवधि में 49,968 करोड़ रुपये बाहर से मिले। विदेशी धन पाने वाले इन संगठनों की संख्या 2009-10 में 21508 थी। मार्क की बात है कि विदेशी धन केवल धनी देशों से ही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जाम्बिया, कांगो आदि से भी आया है। गृह मंत्रालय के अनुसार 2009-10 के दौरान नेपाल ने 12 करोड़ चीन ने 2.8 करोड़ अफगानिस्तान ने 1.9 करोड़ पाकिस्तान ने 1.2 करोड़ और बांग्लादेश ने 86 लाख रुपए दिए।

xj&l jdkjh l xBuk dk bfrgkl %

प्राचीनकाल से ही भारत में स्वैच्छिक कार्य और समाज सेवा की गौरवशाली परम्परा रही है। दूसरे शब्दों में कहे तो परोपकार, गरीबों, दुःखीजनों की सेवा और जरूरतमन्द लोगों की सहायता भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रही है तथा धर्म-कर्म की भाषा में इसे पुण्य की संज्ञा दी गई है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जरूरतमंद लोगों की सहायता तथा सूखा बाढ़ या महामारी आदि के समय गाँव के लोग एक-दूसरे की मदद करते थे और सहायता की ये सारी गतिविधियाँ मन्दिर, आश्रम जैसी संस्थाओं के माध्यम से संचालित होती थीं।

19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में समाज सेवा के इन कार्यों को एक संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इस दौरान जाति प्रथा की कठोरता को कम करने, विधवा विवाह को बढ़ा देने, दहेज प्रथा के उन्मूलन, अनाथ एवं निःसहाय लोगों की सहायता तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई संगठनों का जन्म हुआ। पूर्वी भारत में राजा राममोहन राय ने आत्मीय समाज (1815), यूनीटेरियन समिति (1822) और ब्रह्मा समाज (1828) की स्थापना की। पश्चिम भारत में दादा भाई नौरोजी ने समाज सेवा के कार्यों को अगे बढ़ाया। उन्होंने 1849 से 1865 के दौरान महिला शिक्षा और धार्मिक सुधार को बढ़ावा देने हेतु कई प्रयास किए।

tutkfr dh vo/kkj .kk%

भारत वास्तव में विविधताओं वाला देश है जहाँ विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जिनकी पृथक संस्कृति, पृथक धर्म, पृथक विश्वास एवं आस्थाएँ हैं। इन्हीं समुदायों में से एक जनजाति समुदाय जिसकी देश की सामाजिक आर्थिक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर में विशिष्ट भूमिका रही है। इस जनजाति समुदाय को विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग नामों की संज्ञा दी है जैसे दृमार्टिन एवं रिजले ने “आदिवासी” हट्टन ने इन्हें “आदिम जातियाँ” सर वेंस ने इन्हें पर्वतीय आदिम जातियाँ या वन्य जातियाँ घुरिये ने इन्हें “पिछड़े हुए हिंदू” तथा वनों में रहने के कारण गांधीजी ने इन्हें गिरिजन के नाम से पुकारा है।

i fj Hkk"kk%

डॉ. मजुमदार ने कहा है कि “आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है, जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है। ये वे प्राचीन लोग हैं, जिनके नैतिक अधिकार और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं, वे सबसे पहले यहाँ आए।” भारतीय संविधान में इन्हें “अनुसूचित जनजाति” के नाम से सूचीबद्ध किया गया है।

इम्पीरियल गजेटियर के अनुसार— “जनजाति परिवार या परिवारों का एक ऐसा समुदाय है जिसका एक सामान्य नाम होता है, इसमें रहने वाले लोग एक सामान्य बोली बोलते हैं जो एक सामान्य भू-भाग पर रहने का दावा करते हो अथवा जो हमेशा अन्तर्विवाह नहीं करते है भले ही प्रारंभ करता रहे हो।”

डॉ. रिर्वर्स के अनुसार— “जनजाति सरल प्रकार का सामाजिक समूह होता है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जनजाति एक निश्चित भू-भाग में रहने वाला एक आदिम मानव समूह है जो एक सामान्य भाषा, धर्म, प्रथा, परम्परा व्यवसाय और अन्य सामाजिक नियमों द्वारा एक सूत्र में बंधकर एक सामाजिक संगठन को जन्म देता है।

tutkfr , oafodkl %

जनजातिय विकास की चर्चा करने से पूर्व हमें दो शब्दों जनजाति एवं विकास को परिभाषित करना होगा।

मानवशास्त्रीय साहित्य में ऐसे समुदायों को जनजाति की श्रेणी में रखा गया है जिनमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं — कम जनसंख्या घनत्व, आदिम धर्म, निम्न स्तर, भिन्न संस्कृति, संकोचित भावना, आदि अर्थव्यवस्था, आदिम राजनीतिक व्यवस्था, प्रौद्योगिकी लिपि का अभाव तथा अन्य सामाजिक समूहों की दूरी। वास्तव में द्वीपीय समूहों को छोड़कर देश का कोई भी सामाजिक समूह इन लक्षणों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता। भारत में प्रायः ऐसे सामाजिक समूहों को जनजाति कहा जाता है जिन्हें राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा जनजाति घोषित किया गया है। दूसरे शब्दों में प्रायः भारतीय जनजातियाँ ‘अनुसूचित जनजातियाँ’ हैं। बहुत सी जनजातियाँ ऐसी हैं जिन्हें अनुसूचित नहीं किया गया है। इसलिए ऐसी कई जनजातियों को संविधान के अंतर्गत ‘अनुसूचित जाति’ में रखा गया है इसलिए जनजातियों की इस चर्चा में वे सम्मिलित नहीं हैं।

विकास को परिभाषित करना एक टेड़ी खीर है परन्तु अलग-अलग विज्ञानों ने इसी अलग-अलग प्रकार से परिभाषित किया है। प्रायः पाठ्य पुस्तकों में विकास की परिभाषा नहीं दी जाती।

'kks/k i) fr%

प्रस्तुत अध्ययन में डूंगरपुर में जनजातीय समाज के विकास में गैर-सरकारी संगठनों का अध्ययन किया गया है कुछ गैर सरकारी संगठन डूंगरपुर जिले में करीब 5-8 वर्षों में विकासोन्मुख गतिविधियों में संलग्न है जिले में जनजातीय समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शोधकर्ता द्वारा दैव निदर्शन पद्धति की नियमित अंकन प्रणाली द्वारा जिले में गैर-सरकारी संगठनों का चयन किया गया है। डूंगरपुर में 1. वागदरी जनसेवा मण्डल, 2. मोरुका चेरिटेबल ट्रस्ट, 3. राजस्थान बाल कल्याण समिति 4. राजस्थान आदिवासी संघ 5. पीडों माडा सांधान, 6. आकार सेवा संस्थान, 7. महावीर इंटरनेशनल, 8. चेतना मुखबधिर व ट्राइफेड संस्थान, 10. वागड़ जनजागृति संस्थान, 11. राजस्थान सेवा संघ, 12. जन-चेतना संस्थान, 13. मानव सेवा संस्थान, 14. परयास संस्थान, 15. मुस्कान संस्थान, 16. सेव द चिल्ड्रन संस्थान, 17. देव सोमनाथ सेवा समिति, 18. गुरुकुल संस्थान, 19. कर्म श्री संस्थान, 20. महिला आर्थिक उत्थान संस्थान।

mi's ; %

1. गैर सरकारी संगठन जनजातीय समाज के विकास हेतु मोताणा, नात्रा, मृत्यूभोज, आदि सामाजिक बुराइयों के निराकरण हेतु क्या प्रयास कर रही है इसकी जानकारी प्राप्त करना।
2. गैर सरकारी संगठन जनजातीय समाज के विकास हेतु शिक्षा के क्षेत्र में कैसे कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों का संचालन कर रही है इसकी जानकारी प्राप्त करना।
3. रोजगार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन किस प्रकार के प्रयास कर रही है इसकी जानकारी प्राप्त करना।
4. गैर सरकारी संगठन स्वास्थ्य सुधार सम्बन्धित क्या-क्या प्रयास कर रही है। इसकी जानकारी प्राप्त करना।
5. रोजगार एवं व्यवसाय को बढ़ाने के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठन की भूमिका क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त करना।

i kdYi uk, j %

प्राकल्पना के निर्माण से शोधकर्ता अन्धकार एवं भटकाव से दूर रहता है। XMs , Oa gkV ने भी लिखा है प्राकल्पना अनुसन्धान और सिद्धान्त के बीच एक आवश्यक कड़ी है जो ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायक होती है।

ckxkMI l ने बताया है "एक प्राकल्पना एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाता है।

किसी भी अध्ययन को सही मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाना आवश्यक है। प्राकल्पनाएं मूलरूप से वे कथन हैं जिनका सत्यापन किया जाना शेष है। इस अध्ययन से सम्बन्धित जो प्राकल्पना व्याप्त है। उन्हें हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे।

i æq[ k mi dYi uk, j %

1. गैर सरकारी संगठनों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि स्थानीय सामाजिक व्यवस्था से मेल खाती हुई होती है।
2. जनजातीय समाज के विकास के लिए सरकारी संगठनों द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों की तुलना यदि उसका दायित्व गैर सरकारी संगठनों को सौंपा जाये तो वे जल्दी सफलता प्राप्त करने में सक्षम होती है।
3. गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जाने वाले नवीन कार्यक्रमों में जनजातीय समाज के व्यक्ति अधिक रुचि रखते हैं अतः कई कठिनाइया आसानी से दूर की जा सकती है।
4. जनजातीय समाज के विकास में गैर सरकारी संस्थाएँ समाज की मूल संस्कृति बचाये रखने हेतु के साथ नवीन परिवर्तनों में सामंजस्य शीघ्र स्थापित करने में प्रभावी भूमिका रखती है।

vuq[ kku dk egRo%

इस शोध से डूंगरपुर जिले के जनजातीय समाज में गैर सरकारी संगठनों के कार्यों का मूल्यांकन होगा, ग्रामीणों के मूलभूत क्षेत्रों में कार्य करने के लिए गैर सरकारी संगठनों की भूमिका शासन के कार्यों के पूरक के रूप में होता है। गैर सरकारी संगठनों का समग्र ग्रामीण विकास एवं इससे सम्बन्धित कार्यक्रमों में योगदान को रेखांकित करते हुए कहा गया है कि ऐसे गैर सरकारी संगठन जो स्थानिय स्तर पर कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास में अधिक मददगार हो सकते हैं। साथ ही पंचवर्षिय योजना में इसके बारे में विस्तृत रूप रेखा दी गयी है उसमें केवल यही नहीं बताया है कि गैर सरकारी संगठन ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन में क्या और कैसे योगदान कर सकती हैं बल्कि इस आवश्यकता

पर भी जोर दिया गया है कि गैर सरकारी संगठनों के साधनों एवं समताओं के दायरे में व्यवसायिक कार्यक्षमता एवं प्रबन्धकिय विशेषज्ञता का विकास स्वयं सेवा के व्यापककरण के लिए किया जाना चाहिए ताकि शासकीय आवश्यकताओं का उत्तरदायित्व वहन करने में सक्षम हो सके। (सातवी योजना 1985-90 जिल्द 11 योजना आयोग भारत सरकार नयी दिल्ली पृष्ठ 68-69) डूंगरपुर और बाँसवाड़ा जिले विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं के माध्यम से बिजली, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, सड़क, स्कूल एवं स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों की व्यवस्था की जा रही है। बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी को न्यून स्तर पर लाने के लिए विकास योजनाएँ गैर सरकारी संगठनों के माध्यमों से क्रियान्वित की जा रही हैं। जनजातीय समाज के विकास में गैर सरकारी संगठनों द्वारा किये गये कार्यों का कहां तक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जनजातिय समाज के स्थान में उनकी क्या भूमिका रही है। व्यक्ति में आत्मविश्वास जगाने स्वावलम्बी बनाने, समस्याओं के प्रति सही समझदारी पैदा करने, सामुहिक पहल को प्रेरित करने के सम्बन्धित क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका रही है के सन्दर्भ में अध्ययन करना शिक्षा व अज्ञानता के कारण जनजातीय समाज के लोग विकास योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उन तक लाभ पहुंचाने में गैर सरकारी संगठनों का क्या योगदान रहा है, इससे अवगत हो पायेंगे।

निःसंदेह आजादी के बाद से ही सरकारी द्वारा आदिवासी विकास के लिए निरन्तर योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। किन्तु इन सब प्रयासों के बावजूद यह कटु सत्य है कि देश की 8.6 प्रतिशत जनजाति आबादी की प्रगति लक्ष्यानु रूप नहीं हो पाई है। आज भी आदिवासी अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, सिंचाई, पेयजल, सड़क, सामाजिक सुरक्षा जैसे आधारभूत क्षेत्रों में स्थितियां अपेक्षित लक्ष्यों से बहुत नीचे हैं। आदिवासी विकास योजनाओं का लक्ष्यानु रूप परिणाम न मिल पाने के कारणों को देखा जाए तो वे, शासकीय मशीनरी के द्वारा इस समुदाय की प्राथमिक आवश्यकताओं तथा समस्याओं की ओर ध्यान न देना, कार्यों के प्रत्येक स्तर में समुदाय की भागीदारी व जनसहयोग को न लेना, जिस तरह यह समुदाय अपने विकास के लिए विकास की प्रक्रिया को चाहता है उस तरह की प्रक्रिया को न अपनाया जाना, कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति, सामंजस्य का अभाव, कमजोर एवं लचर आपूर्ति व्यवस्था, इस समुदाय में पाई जाने वाली कुरीतियां जो इन्हें आर्थिक रूप से पंगु बना देती है कि ध्यान न देना जैसे कारण रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि कोई भी विकास कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें वे लोग शामिल न हों जिनके विकास के लिए ये कार्यक्रम चलाए जा रहें हैं। विकास का अर्थ सिर्फ योजना बनाकर लागू करना नहीं वरन् लोगों को स्वयं अपने विकास के लिए संगठित होकर योजना बनाने योग्य बनाना है। आजादी के बाद से ही विकास कार्यक्रमों के नियोजन एवं संचालन का दायित्व नौकरशाही को सौंपा गया है किन्तु नौकरशाही की अपनी सीमाएँ, समस्याएँ एवं व्यवस्थाएँ हैं।

। nHk%

1. डॉ. उदयसिंह राजपूत (2010) आदिवासी विषय एवं गैर-सरकारी संगठन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ. 2-3
2. विजयशंकर उपाध्याय एवं गया पाण्डेय (2002) जनजातीय विकास, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृ. 3
3. नरेश कुमार वैद्य (2003), जनजातीय विकास : मिथक एवं यथार्थ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ. 7-16
4. डॉ. उदयसिंह राजपूत, पूर्वोक्त, पृ. 3-7
5. एस.एल. पालीवाल (2000), जनजाति विकास के पंचशील सिद्धान्त : ट्राइब वर्ष 35, अंक - 3-4, पृ. 1-9
6. विजयशंकर उपाध्याय, गया पाण्डेय, पूर्वोक्त, पृ. 8-13
7. नरेश कुमार वैद्य (2003), जनजातीय विकास : मिथक एवं यथार्थ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ. 7-16